◆ ADVT ◆
यहाँ विज्ञापन दें
98700 06472 · need24.digital

NEED24 NEWS
हर ख़बर, हर शहर

# नीड 24 न्यूज़

हर खबर, हर शहर

◆ ADVT ◆
यहाँ विज्ञापन दें
98700 06472 · need24.digital

DIGITAL E-PAPER

PRGI APPLICATION UNDER PROCESS
Application No. T/GJ/2026/0619/2304/1577

GST
GSTIN 24CINPG0564Q1ZT

UDYAM REGISTERED
UDYAM-GJ-14-0003714

◆ DIGITAL NEWS NETWORK ◆
भारत का भरोसेमंद बहुभाषी डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क
11+ Languages | 24×7 Live | e-Paper Daily

हमारा App डाउनलोड करें
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

www.need24.digital
info@need24.in
+91 98700 06472
FOLLOW US:

तेज़ | सटीक | निष्पक्ष | जनहित में | सच की आवाज़ | जन-जन की आवाज़ | निडर पत्रकारिता



नौकरी

## कैप्टन संजय की नई मर्चेंट नेवी पहल से हिमाचल की बेटियों को मिले नई करियर के रास्ते



कैप्टन संजय, एक अनुभवी समुद्री पेशेवर, ने हिमाचल की बेटियों के लिए मर्चेंट नेवी में करियर के नए रास्ते खोलने के उद्देश्य से एक नई पहल की घोषणा की है।

यह कार्यक्रम प्रशिक्षण और भर्ती के अवसर प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, जिससे राज्य की महिलाओं को समुद्री करियर अपनाने का मौका मिले।

मैरिटाइम शिक्षा तक पहुँच और उद्योग के भर्ती अधिकारियों से जोड़कर, यह पहल हिमाचल की महिलाओं के लिए रोजगार विकल्पों का विस्तार करने का लक्ष्य रखती है।

### स्कूल की शीतकालीन छुट्टियाँ 2026-27: राज्यवार तिथियाँ और पुनः खुलने का शेड्यूल जारी

टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2026-27 शैक्षणिक वर्ष के लिए भारत के प्रत्येक राज्य में स्कूलों की शीतकालीन छुट्टियों के कैलेंडर को विस्तृत रूप से प्रकाशित किया है। इस गाइड में बताया गया है कि अधिकांश राज्यों में छुट्टियाँ दिसंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होती हैं और जनवरी के पहले सप्ताह में स्कूल पुनः खुलते हैं,

### हिमाचल की सेब की खेती को बदलते बर्फबारी पैटर्न से खतरा

हिमाचल प्रदेश की सेब की खेती, जो राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बदलते जलवायविक परिस्थितियों के कारण असामान्य चुनौतियों का सामना कर रही है। हाल के रुझानों से पता चलता है कि पहाड़ी इलाकों में बढ़ती गर्मी से पारंपरिक बर्फबारी के पैटर्न बदल रहे हैं, जिन पर सेब के बागों के स्वस्थ विकास का निर्

कृषि

### हिमाचल प्रदेश ने हल्दी का MSP ₹170, गेहूँ का ₹90 कर बढ़ाया



हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बदलाव की घोषणा की है। हल्दी का MSP अब ₹170 और गेहूँ का MSP ₹90 कर दिया गया है। यह निर्णय जीवानटसहन्यूज़ द्वारा रिपोर्ट किया गया है और किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है। नई दरें आगामी फसल कटाई के दौरान लागू होंगी, जिससे उत्पादकों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम किसानों की आय बढ़ाने और इन फसलों की आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर करने के लिए उठाया गया है।

MSP प्रणाली किसानों को बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करती है। हल्दी और गेहूँ के लिए मूल्य वृद्धि से इन फसलों की लाभप्रदता में सुधार होगा, जो राज्य की कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह घोषणा व्यापक उपायों का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य किसानों की चिंताओं को दूर करना और कृषि विकास को सुदृढ़ करना है।

किसान संगठनों सहित सभी हितधारकों को नई MSP लागू होने की प्रक्रिया पर करीबी नज़र रखने की उम्मीद है। संशोधित MSP की जानकारी राज्य की कृषि विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले आगामी अधिसूचनाओं में प्रकाशित होगी।

अपराध

### हिमाचल प्रदेश के सीएम ने 3 साल में 1,300 से अधिक बलात्कार मामलों की सूचना दी



हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के एक हालिया सत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले तीन वर्षों में राज्य में 1,300 से अधिक बलात्कार मामलों की रिपोर्ट दर्ज हुई है। यह आंकड़ा पुलिस और न्यायालयों में दाखिल सभी शिकायतों को सम्मिलित करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संख्या केवल दर्ज किए गए मामलों को दर्शाती है और प्रत्येक मामले की गहन जांच की आवश्यकता है। उन्होंने रोकथाम के उपायों को सुदृढ़ करने, न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ करने और पीड़ितों को बेहतर सहायता प्रदान करने की बात की।

महिला अधिकार समूह और नागरिक समाज ने राज्य में, विशेषकर दूरदराज़ और पर्यटन क्षेत्रों में, सुरक्षा तंत्र को बेहतर बनाने की लगातार मांग की है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि प्रशासन मौजूदा नीतियों की समीक्षा कर रहा है और इस समस्या को शीघ्र हल करने के लिए अतिरिक्त संसाधन आवंटित करेगा।

सरकारी योजना

### हिमाचल प्रदेश में सड़क माल परिवहन पर पर्यावरणीय शुल्क लागू



हिमाचल प्रदेश की राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्य के भीतर सड़क द्वारा परिवहन किए जाने वाले सभी माल पर पर्यावरणीय शुल्क लगाने का प्रस्ताव मंजूर किया है। यह शुल्क प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए आय उत्पन्न करने और सतत परिवहन बुनियादी ढाँचे को समर्थन देने के उद्देश्य से लगाया जाएगा।

अधिकारियों ने बताया कि यह शुल्क माल परिवहन शुल्क के प्रतिशत के रूप में गणना किया जाएगा और राज्य राजमार्गों व मुख्य arterial सड़कों पर चलने वाले व्यावसायिक ट्रकों पर लागू होगा। यह कदम हिल स्टेशन के क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनज़र उठाया गया है, जहाँ वाहन उत्सर्जन पर्यावरणीय गिरावट में प्रमुख योगदान देता है।

उद्योग प्रतिनिधियों को सूचित किया गया है कि नया शुल्क लॉजिस्टिक लागत में वृद्धि कर सकता है, पर सरकार का मानना है कि कम उत्सर्जन और बेहतर सड़क स्थितियों के दीर्घकालिक लाभ अल्पकालिक वित्तीय प्रभाव से अधिक हैं।

अंतिम अधिसूचना और अनुपालन निगरानी तंत्र की स्थापना के बाद यह नीति इस वर्ष के अंत तक लागू की जाएगी।

शिक्षा

### हिमाचल प्रदेश ने स्कूल क्लस्टर प्रणाली लागू की



हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्कूल क्लस्टर प्रणाली शुरू करने की घोषणा की, जिससे स्कूलों के प्रबंधन में संरचनात्मक बदलाव आएगा। इस नई व्यवस्था के तहत स्कूलों को समूहों में बाँटा जाएगा ताकि निगरानी और संसाधन साझा करने में समन्वय स्थापित हो सके। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर शैक्षिक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाएगा। कार्यान्वयन की समयसीमा के बारे में अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, पर यह नीति स्कूलों की निगरानी में समानता लाने की उम्मीद है। शिक्षा क्षेत्र के हितधारकों ने इस पहल का स्वागत किया है, इसे राज्य में स्कूल प्रशासन को अधिक कुशल बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना गया है।

विज्ञान

### हिमाचल प्रदेश में साईबेरियन प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति



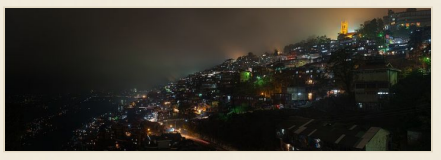
हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पक्षी प्रेमियों ने साईबेरिया में प्रजनन करने वाले कई प्रवासी पक्षियों के आगमन की पुष्टि की है। ये sightings दिसंबर के शुरुआती हफ्तों में दर्ज हुईं, जो इन प्रजातियों के सामान्य शीतकालीन प्रवास के साथ मेल खाती हैं। देखे गए पक्षियों में कई जलपक्षी और वॉटरफ़ॉड शामिल हैं, जो साईबेरिया की कठोर सर्दी से बचने के लिये हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। इनकी उपस्थिति राज्य की समृद्ध जैव विविधता में इजाफा करती है और इस मौसम में प्रकृति प्रेमियों को आकर्षित करने की संभावना है।

स्थानीय वन अधिकारी इस प्रवाह को नोट कर रहे हैं और आवासों की निगरानी कर रहे हैं ताकि न्यूनतम व्यवधान हो। यह आगमन इको-टूरिज़्म को भी बढ़ावा देता है, कई ट्रेकिंग और बर्ड-वॉचिंग समूह उच्च altitude वाले झीलों और दलदल क्षेत्रों की यात्रा की योजना बना रहे हैं।

अधिकारियों ने दर्शकों से पक्षियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने और वन्यजीव तथा नाज़ुक अल्पाइन पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है।

बिज़नेस

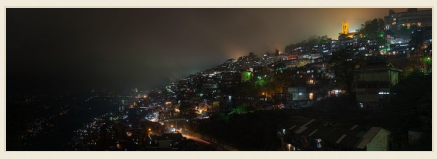
### हिमाचल प्रदेश ने शिमला, सोलन, सिरमौर और कांगड़ा में चार नई टाउनशिप की योजना घोषित



हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह शिमला, सोलन, सिरमौर और कांगड़ा जिलों में प्रत्येक एक नई टाउनशिप विकसित करेगी। यह पहल राज्य में संगठित शहरी बुनियादी ढाँचा बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है।

अधिकारियों के अनुसार, इन टाउनशिपों को आधुनिक सुविधाओं के साथ योजना-बद्ध किया जाएगा, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक और सार्वजनिक क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा और मौजूदा सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इन परियोजनाओं से निर्माण कार्यों में रोजगार सृजन और सहायक आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

## हिमाचल प्रदेश ने शिमला, सोलन, सिरमौर और कांगड़ा में चार नई टाउनशिप की योजना घोषित



हिमाचल प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि वह शिमला, सोलन, सिरमौर और कांगड़ा जिलों में प्रत्येक एक नई टाउनशिप विकसित करेगी। यह पहल राज्य में संगठित शहरी बुनियादी ढाँचा बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है।

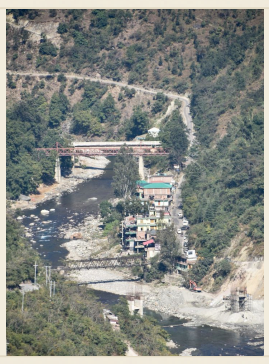
अधिकारियों के अनुसार, इन टाउनशिपों को आधुनिक सुविधाओं के साथ योजना-बद्ध किया जाएगा, जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक और सार्वजनिक क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा और मौजूदा सड़क नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इन परियोजनाओं से निर्माण कार्यों में रोजगार सृजन और सहायक आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

रियल एस्टेट विशेषज्ञ इस कदम को हिमाचल में व्यवस्थित आवास और व्यावसायिक स्थानों की बढ़ती मांग के जवाब में देख रहे हैं, जो जनसंख्या वृद्धि और पर्यटन से प्रेरित है। सरकार ने अभी तक टाउनशिपों के विस्तृत समय-सारिणी या लागत अनुमान सार्वजनिक नहीं किए हैं।

आगे की जानकारी आगामी नीति दस्तावेज़ों में आएगी, और कार्यान्वयन में राज्य एजेंसियों, स्थानीय प्राधिकरणों और निजी विकासकों के बीच समन्वय आवश्यक होगा।

नौकरी

## हिमाचल में सरकारी पदों की हजारों रिक्तियां



हिमाचल प्रदेश सरकार ने बताया कि विभिन्न विभागों में हजारों सरकारी पद अभी भी खाली हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। ये रिक्तियां प्रशासनिक, तकनीकी और सहायक सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं।

अधिकारी योग्य उम्मीदवारों से अनुरोध कर रहे हैं कि वे आधिकारिक भर्ती पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें, क्योंकि सरकार जल्द ही कई भर्ती अभियान शुरू करने की योजना बना रही है। इन पदों में क्लर्क, इंजीनियर, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विविध कार्य शामिल हैं।

पदों की भरपाई में देरी के कारण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में रुकावट आई है, इसलिए सरकार ने चयन प्रक्रिया को तेज करने और आगामी महीनों में अतिरिक्त परीक्षा आयोजित करने का वचन दिया है।

यह जानकारी स्थानीय समाचार साइट जीवंतुशा द्वारा प्रकाशित की गई है, जो नौकरी चाहने वालों को राज्य की रोजगार वेबसाइट पर अपडेट और आवेदन की अंतिम तिथियों की निगरानी करने की सलाह देती है।

यात्रा

## हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने पर्यटन विकास को स्थानीय समुदायों के हित में रखने की अपील की



हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने हालिया प्रेस ब्रीफ़िंग में कहा कि राज्य में पर्यटन का विस्तार स्थानीय समुदायों की इच्छाओं के साथ तालमेल में होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अनियंत्रित विकास इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर को कमजोर कर सकता है, जो इसे पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाता है।

हुए, उन्होंने ज़ोर दिया कि विकास योजनाओं में उन लोगों की राय को शामिल किया जाना चाहिए, जिनकी आजीविका इस क्षेत्र पर निर्भर है। उन्होंने प्रभाव आकलन और लाभ-साझाकरण के पारदर्शी तंत्र की मांग की।

नीति निर्माताओं, निजी निवेशकों और पर्यटन एजेंसियों से स्थानीय पंचायतों और समुदाय के नेताओं के साथ सीधे संवाद स्थापित करने का आग्रह किया गया, ताकि बुनियादी ढाँचा, प्रचार और निवेश पहल स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हों। राज्यपाल के इस बयान ने सतत पर्यटन पर राष्ट्रीय चर्चा को प्रतिबिंबित किया है, जिसमें आर्थिक लाभ के साथ सामाजिक समानता को भी महत्व दिया गया है।

समुदाय के हितों के साथ पर्यटन रणनीतियों को संरेखित करके, हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए सभी के लिए समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

नौकरी

## एचपी पटवारी 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध



हिमाचल प्रदेश सार्वजनिक सेवा आयोग (HPPSC) ने 2026 के पटवारी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अब आधिकारिक HPPSC वेबसाइट के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को पोर्टल में लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी, फिर 'डownload Admit Card' बटन पर क्लिक करना होगा। प्राप्त PDF फ़ाइल को प्रिंट कर परीक्षा केंद्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

आयोग ने सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वे एडमिट कार्ड पर अपना नाम, फोटो और परीक्षा केंद्र जैसी जानकारी को सावधानीपूर्वक जाँचें और किसी भी त्रुटि की तुरंत सूचना दें। एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रति मोबाइल में भी रखें, ताकि किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति में बैकअप उपलब्ध हो।

राजनीति

## हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत की



हिमाचल प्रदेश विधानसभा आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत करेगी, जिससे ठंड के महीनों में विधायी कार्यवाही का क्रम शुरू होगा। विधायक शिमला स्थित विधानसभा भवन में इकट्ठा होकर बकाया विधेयकों, बजट आवंटनों और राज्य नीतियों पर चर्चा करेंगे।

राज्य सरकार द्वारा बुलाए गए इस सत्र में प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आवाज़ उठाने का अवसर मिलेगा, जिसमें पर्यटन, कृषि और बुनियादी ढाँचा विकास शामिल हैं। कई समिति बैठकों का आयोजन किया जाएगा ताकि प्रस्तावों की विस्तृत जांच के बाद उन्हें सदन में चर्चा के लिए लाया जा सके।

विशेषज्ञों का मानना है कि शीतकालीन सत्र में प्रदेश की मौसमी पर्यटन और पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी जैसी प्रमुख चुनौतियों को संबोधित किया जाएगा। सत्र कई हफ्तों तक चलने की संभावना है, जिसके बाद निर्णयों का सार जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

सत्र की शुरुआत सरकार की नियमित विधायी प्रक्रिया को जारी रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे कठोर सर्दी के बावजूद शासन में कोई रुकावट नहीं आएगी।

## हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखु ने मंत्री नेगी का बचाव किया, सेना के कथन पर



सेना के कथन के बाद, भाजपा ने मंत्री नेगी के कार्यों पर सवाल उठाया। इसके जवाब में, मुख्यमंत्री सुकु ने मंत्री का समर्थन करते हुए कहा कि उनके निर्णय राज्य की नीतियों के अनुरूप हैं।

सुकु ने जोर दिया कि नेगी के कदम जनता के हित में थे और भाजपा के आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने विपक्ष को राजनीतिक आक्रमण के बजाय रचनात्मक संवाद पर ध्यान देने का आग्रह किया।

यह घटना हिमाचल प्रदेश में शासक दल और विपक्ष के बीच चल रहे राजनीतिक तनाव को दर्शाती है, जिसमें मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट सदस्यों के प्रति अपना समर्थन दोहराया है।

अपराध

## हिमाचल प्रदेश: भारत की दवा की दवा बनती है नकली दवाओं का केंद्र



हिमाचल प्रदेश, जिसे दवाओं के लिए जाना जाता है, अब नकली दवाओं के उत्पादन और तस्करी का प्रमुख केंद्र बन गया है।

हालिया खुफिया रिपोर्टों में राज्य भर में दर्जनों गुप्त कार्यशालाओं की पहचान की गई है, जो लोकप्रिय ब्रांडों की नकल करते हुए भी चिकित्सीय प्रभावहीन दवाएं बनाती हैं।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने संचालन को तेज किया है, समन्वित रैड्स के दौरान बड़ी मात्रा में नकली टैबलेट और सिरप जब्त किए और कई प्रमुख ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया।

नकली दवाओं के बढ़ते प्रसार से सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा है, जिससे उपचार के परिणाम प्रभावित होते हैं और राज्य की दवा प्रतिष्ठा पर विश्वास घटता है।

सरकारी योजना

## हिमाचल प्रदेश ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए प्रोत्साहन ₹5 करोड़ तक बढ़ाया



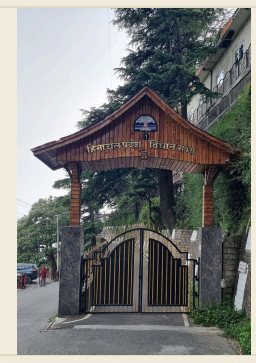
हिमाचल प्रदेश सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है, जिसमें पुरस्कार राशि ₹5 करोड़ तक बढ़ाई गई है। यह कदम राज्य के खेल क्षेत्र को नई दिशा देने के उद्देश्य से लिया गया है।

नई योजना के तहत, स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ी को ₹5 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा, साथ ही प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त सहायता भी बजट में शामिल की गई है। यह कदम पहले के रजत और कांस्य पदक विजेताओं के लिए निर्धारित ₹2 करोड़ और ₹1 करोड़ के प्रोत्साहन को आगे बढ़ाता है।

खेल अधिकारियों का कहना है कि इस उच्च पुरस्कार से राज्य में और अधिक प्रतिभा आकर्षित होगी और खिलाड़ियों को ओलंपिक लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी। सरकार ने खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कोचिंग और चिकित्सा सुविधाओं को भी सुदृढ़ करने की योजना बनाई है।

यह घोषणा हिमाचल प्रदेश की खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के प्रयासों के अनुरूप है।

## हिमाचल प्रदेश ने निवेश मंजूरी को आसान बनाने के लिये बिल पेश किया



हिमाचल प्रदेश सरकार ने निवेशकों के लिये प्रक्रिया को सरल बनाने और मंजूरी को तेज करने हेतु एक विधायी बिल पेश किया है। यह प्रस्ताव राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है और कई विभागीय अनुमोदनों में मौजूद जटिलताओं को दूर करने का लक्ष्य रखता है।

अधिकारियों के अनुसार, इस बिल के तहत एक सिंगल-विंडो प्रणाली स्थापित की जाएगी जिससे कई विभागीय अनुमोदनों को एक ही मंच पर संकलित किया जा सके, जिससे निवेश के लिये आवश्यक समय और कागजी कार्य कम हो जाएगा। यह कदम पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निजी एवं सार्वजनिक पूंजी को आकर्षित करने के लिये उठाया गया है।

अब इस विधेयक पर विधायकों द्वारा चर्चा की जाएगी, और सरकार का मानना है कि यह नई व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की व्यापार सुगमता रैंकिंग को सुधारने में मदद करेगी। वोट से पहले हितधारकों को अपने सुझाव देने का अवसर दिया गया है।

कृषि

## भारत का पहला संगठित गधे का फार्म खुला, दूध की कीमत रु 10,000 प्रति लीटर



एक नया पशु पालन उद्यम भारत के पहले संगठित गधे के फार्म के रूप में शुरू हुआ है। इस फार्म का लक्ष्य गधे का दूध उत्पादन करना है, जिसे रु 10,000 प्रति लीटर की प्रीमियम कीमत पर बेचा जाएगा। संरचित आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करके, फार्म गधे के दूध के लिए एक भरोसेमंद बाजार बनाना चाहता है, जिसे इसके पोषण लाभों के कारण विशेष महत्व दिया गया है।

यह पहल उन किसानों के लिए नई आय के अवसर खोलने की उम्मीद रखती है जो फार्म के दिशानिर्देशों के तहत गधे पालने को तैयार हैं। उत्पादन को एकत्रित करके और गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करके, फार्म गधे के दूध को एक व्यावसायिक वस्तु बनाना चाहता है।

उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च कीमत गधे के दूध की सीमित उपलब्धता और सौंदर्य एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में बढ़ती मांग को दर्शाती है। फार्म का उद्घाटन भारत के डेयरी और पशुपालन क्षेत्र को विविधता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

हितधारकों का अनुमान है कि इस मॉडल को अन्य क्षेत्रों में दोहराया जा सकता है, जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि और वैकल्पिक पशुपालन प्रथाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

फार्म के प्रबंधन ने उत्पादन क्षमता के विस्तृत आँकड़े नहीं बताए हैं, लेकिन ध्यान गधे के दूध के उत्पादकों और खरीदारों के लिए एक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर है।

## शिमला में शीतकालीन यात्रा प्रदर्शनी का उद्घाटन, गवर्नर ने हिमालयी पर्यटन को बढ़ावा दिया



हिमाचल प्रदेश के गवर्नर ने शिमला में शीतकालीन यात्रा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जो ठंडे मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक नई पहल का हिस्सा है।

यह प्रदर्शनी शिमला के एक प्रमुख स्थल पर आयोजित की गई, जहाँ यात्रा एजेंसियाँ, होटल और स्थानीय व्यवसाय शीतकालीन यात्रा पैकेज, दर्शनीय मार्ग और क्षेत्रीय आकर्षण प्रस्तुत करते हैं।

उद्घाटन के दौरान गवर्नर ने हिमालयी क्षेत्र के सतत विकास के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि शीतकालीन पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का समर्थन करता है।

अधिकारियों का मानना है कि यह कार्यक्रम भारत और विदेशों से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करेगा, जिससे शिमला की अनूठी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को बढ़ावा मिलेगा।

राजनीति

## विजय सिंह मानकोटिया: सैन्य सेवा और हिमाचल राजनीति में अनमोल योगदान



विजय सिंह मानकोटिया ने हिमाचल प्रदेश के सैन्य और राजनीतिक परिदृश्य में एक अद्वितीय छाप छोड़ी है। उनका करियर कर्तव्य के प्रति समर्पण से परिभाषित होता है, जिसमें उन्होंने सैन्य वर्दी से लेकर सार्वजनिक सेवा तक ईमानदारी से काम किया।

एक सैनिक के रूप में, मानकोटिया ने अनुशासन और सेवा के मूल्यों को अपनाते हुए राष्ट्र की सेवा की। सशस्त्र बलों में उनकी यह पृष्ठभूमि उनके बाद की राजनीतिक गतिविधियों के लिए एक मजबूत आधार बनी।

हिमाचल की राजनीति में, उन्हें अपने सिद्धांतों पर अडिग रुख और क्षेत्र के लोगों से गहरे संबंधों के लिए जाना जाता है। उनका विरासत अक्सर 'सैनिक' के रूप में वर्णित की जाती है, जो उनके सैन्य अनुभव और राजनीतिक दृढ़ता दोनों को दर्शाती है।

द इंडियन एक्सप्रेस ने उनकी स्थायी प्रभावशाली भूमिका पर प्रकाश डाला है, यह नोट करते हुए कि हिमाचल प्रदेश में उनकी सैनिक और राजनेता [illegible] पहचान आज भी सम्मान और स्मृति का विषय बनी हुई है।

राजनीति

## हिमाचल CM सुखू: राज्य की आय में 4,000 करोड़ रुपये की वृद्धि



हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखू ने राज्य की आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि राज्य की आय में 4,000 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह घोषणा राज्य की वित्तीय स्थिति में एक सकारात्मक बदलाव को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री ने यह जानकारी प्रस्तुत करते हुए राज्य सरकार द्वारा हासिल की गई आर्थिक प्रगति पर जोर दिया। आय में इस उछाल का कारण बेहतर प्रशासनिक दक्षता और हाल के समय में लागू किए गए प्रभावी संसाधन प्रबंधन रणनीतियाँ बताए गए हैं।

जनकल्याण योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास परियोजनाओं के लिए निधियों के बेहतर आवंटन में सहायक होगी। राज्य नेतृत्व इसे स्थानीय अर्थव्यवस्था की लचीलेपन और मौजूदा वित्तीय नीतियों की प्रभावशीलता का प्रमाण मानता है।

हिमाचल प्रदेश के निवासियों के लिए सार्वजनिक सेवाओं में सुधार और टिकाऊ आर्थिक विकास के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, यह घोषणा सरकार के लिए एक प्रमुख बातचीत का विषय बनी हुई है।

राजनीति

## हिमाचल CM का दावा: कांग्रेस सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति से राज्य कोष में 4000 करोड़ की वृद्धि



हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के वित्तीय प्रगति पर प्रकाश डाला और राजस्व में महत्वपूर्ण वृद्धि का श्रेय प्रशासन की रणनीतिक दृष्टि को दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की 'राजनीतिक इच्छाशक्ति' के कारण राज्य के कोष में 4,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

केंद्रित शासन और कुशल संसाधन प्रबंधन का परिणाम है। उन्होंने यह आंकड़ा सरकार के उस प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य राज्य की आर्थिक नींव को मजबूत बनाना है।

हालांकि, इस राजस्व के स्रोतों के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन नेतृत्व ने इस उपलब्धि को अपनी सक्रिय नीतिगत निर्णयों का प्रमाण बताया है। प्रशासन राज्य के लिए वित्तीय स्थिरता और टिकाऊ विकास पर ध्यान केंद्रित रखने का प्रयास कर रहा है।

बिज़नेस

## भारत ने नया औद्योगिक अधिनियम मंजूर किया, HP उद्योगों में 80% स्थानीय रोजगार अनिवार्य



नवीनतम संसद सत्र में नया औद्योगिक अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत उच्च-प्रदर्शन (HP) उद्योगों में 80% स्थानीय रोजगार अनिवार्य किया गया।

इस कानून के अंतर्गत उन्नत विनिर्माण, प्रौद्योगिकी और उच्च-मूल्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों को अपने कार्यबल का कम से कम 80% भारतीय नागरिकों से बनाना अनिवार्य है। यह कदम विदेशी कुशल श्रम पर निर्भरता घटाने और घरेलू रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।

गया है, जिसमें कंपनियों को वार्षिक कार्यबल रिपोर्ट श्रम व रोजगार मंत्रालय को जमा करनी होगी। निर्धारित कोटा न पूरा करने पर दंड और उससे अधिक करने पर प्रोत्साहन दिए जाएंगे।

विश्लेषकों का अनुमान है कि यह नीति स्थानीय भर्ती में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकती है, विशेषकर उभरते प्रौद्योगिकी केंद्रों में, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिभा अधिग्रहण रणनीतियों को पुनः आकार दे सकती है।

शिक्षा

## आदर्श छात्र-शिक्षक अनुपात के बावजूद हिमाचल के 420 स्कूलों में शिक्षक कमी



द ट्रिब्यून ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में 420 स्कूलों में शिक्षक पद खाली हैं, जबकि राज्य ने छात्र-शिक्षक अनुपात अनुकूल रखा है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि संख्यात्मक मानकों को पूरा करने के बावजूद कक्षाओं में पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं।

शिक्षा विभाग ने स्वीकार किया है कि यह कमी विशेषकर दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है, जहाँ भर्ती हमेशा कठिन रही है। विभिन्न कक्षाओं और विषयों में खाली पदों की वजह से पाठ्यक्रम सुधारों के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

और अनसर्वेड क्षेत्रों में शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की है। अभी तक कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई गई, पर प्राथमिकता इस अंतर को पाटने और अनुकूल अनुपात को वास्तविक कक्षा उपस्थिति में बदलने की है।

बिज़नेस

## हिमाचल प्रदेश के लॉटरी से वार्षिक 16 करोड़ रुपये की आमदनी, ए2ज़ी टैक्सकॉर्प के अनुसार



ए2ज़ी टैक्सकॉर्प लिमिटेड ने अनुमान लगाया है कि हिमाचल प्रदेश में लॉटरी व्यवसाय से वार्षिक लगभग 16 करोड़ रुपये की आमदनी होगी। इस आंकड़े में लॉटरी बिक्री पर लागू मानक GST भी शामिल है, जो राज्य की आय में वृद्धि करेगा।

यह अनुमान सरकार के पारंपरिक करों के अलावा राजस्व स्रोतों को विविधीकरण करने के प्रयासों को दर्शाता है। लॉटरी को बढ़ावा देकर, प्राधिकरण एक विनियमित जुआ विकल्प प्रदान करना चाहते हैं और कर अनुपालन सुनिश्चित करना चाहते हैं।

हालाँकि आय के सटीक समय का उल्लेख नहीं किया गया है, यह प्रक्षेपण लॉटरी क्षेत्र की राज्य की वित्तीय सेहत में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता को उजागर करता है।

## हिमाचल के सीएम ने शहपुर में सिविल अस्पताल की नई इमारत का उद्घाटन किया



हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु ने आज शहपुर सिविल अस्पताल में नई इमारत का उद्घाटन किया। इस विस्तार से ग्रामीण इलाकों के रोगियों के लिए अस्पताल की क्षमता बढ़ेगी। अधिकारियों ने बताया कि इस आधुनिक सुविधा में उन्नत वार्ड, डायग्नोस्टिक सेंटर और बेहतर स्वच्छता व्यवस्था शामिल है।

राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। नई इमारत से नजदीकी अस्पतालों पर रोगियों का दबाव कम होगा और आवश्यक सेवाओं तक तेज़ पहुँच संभव होगी।

स्थानीय लोगों ने इस अवसर पर उपस्थित होकर आशावाद व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि अस्पताल के नवीनीकरण से स्वास्थ्य देखभाल में मौजूदा कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। यह उद्घाटन क्षेत्र में स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ करने के सरकार के संकल्प का एक महत्वपूर्ण कदम है।